Uncorrected/ Not for Publication-04.01.2018

ASC- KGG /3.00/2O

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : जो कि 2015-16 में 140 देशों में 55 वें स्थान पर है। आज हमने इसमें रैंकिंग को बढ़ाया है। इतना ही नहीं मैंने कहा है कि तीन सालों में सरकार ने जो reformative steps लिए हैं, सरकार ने जो निर्णय लिया, सरकार ने जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक प्रकार से अंकुश लगाकर गरीबों के हित में साफ-सुथरी सरकार देने की बात की है, उसी का परिणाम है कि आज दुनिया में Ease of Doing Business में भारत एक साथ तीस पायदान ऊपर गया है। सरकार की यह पॉलिसी, दुनिया की भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसे को बतलाती है कि देश में FDI का जो फ्लो है, वह पिछले तीन सालों में नहीं बल्कि पिछली सरकार की तुलना में भी देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज्यादा हुआ है। वर्ष 2016-17 में 16.2 बिलियन यूएस डॉलर - और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने का कारण है कि सरकार के structural reforms ने देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान की है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इतना ही नहीं अपितु भारत में जो विकास हो रहा है, एक मजबूती के साथ हम लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। यह सरकार की उपलब्धि है कि GST जब से 01 जुलाई, 2017 से लागू हुआ है, देश में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और यह सही था। अगर देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य और केन्द्र सरकार एक साथ आकर एक नई व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं, तो देश का केन्द्रीय कक्ष उसका साक्षी बनना चाहिए, क्योंकि यह भारत के आर्थिक परिवर्तन का बहुत बड़ा संकल्प था। यह उसी संकल्प का परिणाम है कि जीएसटी काउंसिल में आज

तक जितने निर्णय हुए हैं , वे consensus के माध्यम से हुए हैं। देश tax reformer के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है और tax reformer के साथ आगे बढ़ते हुए देश में GST council के कारण जब आकलन बढ़ा है, वहीं भारत में फॉरेन एक्सचेंज यूज़र्स मार्च, 2017 में 317 बिलियन अमरीकन डॉलर था, मार्च, 2016 में 307 बिलियन डॉलर था। आज रिज़र्व बैलेंस से देश में एक अच्छा वातावरण बना है। औद्योगिक विकास संरचना के क्षेत्र को मजबूती मिली है, इसलिए GST के विषय को लेकर सरकार के बजट में प्राथमिकता के विषयों को तय करके देश में हाउसिंग सेक्टर में सरकार ने जो नया विनिवेश खड़ा किया है, हाईवे निर्माण के सेक्टर में सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लेकर देश की आधारभूत संरचना को हाईवे सेक्टर के साथ-साथ कोस्टल कनेक्टिविटी क्षेत्र को बढ़ाया है और औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा ऋण का वितरण किया, वह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और सुगमता के लिए काफी अच्छे मापदंड सिद्ध हुए हैं।

भारत की अर्थव्यवथा और रोजगार वृद्धि के बारे में जब बात की जाती है, तो हमारी सरकार के आने के बाद सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में NSSO के index के साथ ही साथ quarterly index भी देना शुरू किया है। जो मुख्य रूप से रोजगार के आठ क्षेत्र हैं, जिन आठ क्षेत्रों को मानक माना जा सकता है, चाहे manufacturing sector हो, construction sector हो, trade sector हो, transport sector हो, accommodation & restaurant sector हो, IT & BPO sector हो, education sector हो, health sector हो, यदि आप एस्टिमेटेड क्वार्टरली आंकड़े देखेंगे, तो

इसमें रोजगार के बढ़ने की संभावना बढ़ी है। मैं सदन के पटल पर भी इन आंकड़ों को रखना चाहता हूं, ताकि इसके बारे में किसी प्रकार की - ये सारे आंकड़े भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के आंकड़े हैं। सरकार ने जो एक नए तरीके से गणना शुरू की है, ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि आज इन आठों सेक्टर्स में रोजगार क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। जहां तक informal sector की बात है, तो हां, हमारी सरकार आने के बाद निश्चित रूप से इस बात को महसूस किया कि मनरेगा का जो पैसा है, उसके साथ देश के ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई और जल संचयन के साथ मनरेगा को जोड़ना चाहिए।

(2P/SCH पर जारी)

SCH-SKC/3.05/2P

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : इस सरकार के आने के बाद मनरेगा के क्षेत्र में पैसे का ज्यादा निवेश किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्यादा रोज़गारों का सृजन किया गया। पिछले तीन साल में हमारी सरकार ने मनरेगा, पंडित दीन दयाल अंत्योदय योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, Make in India एवं मुद्रा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लाकर देश में informal sector में जो रोज़गार चाहिए था, उस रोज़गार को बढ़ाने का काम किया है। रोज़गार इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ा विषय है। अपने सारे सुधार के विषयों के साथ यह सरकार रोज़गार को बढ़ाने में लगातार आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि आज वैश्विक क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। इस बढ़े हुए विश्वास के साथ, सरकार लोगों के हितों में, गरीबों के हितों में लगातार आगे बढ़ती रहेगी।

हम देख क्या रहे हैं? जब हम यह चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर लोगों के जन-धन खाते खोलें, तो गरीबों के खाते खोले जाने पर आलोचना होती है, जब हम चाहते हैं कि आधार जैसे कानून को लाएं, तो गरीबों को उनके अधिकार दिए जाने पर हमारी आलोचना होती है, जब हम चाहते हैं कि हम ओबीसी के लिए बात करें, तो ओबीसी को उनके अधिकार देने में रोड़े अटकाए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, तो उनके लिए भी रोड़े अटकाने का काम किया जाता है, अर्थव्यवस्था को तो रोकने का काम किया ही जाता है।...(व्यवधान)... इस प्रकार की नीति से देश नहीं चल सकता है। देश को चलाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण चाहिए, देश को चलाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति चाहिए, देश को चलाने के लिए देश के गरीबों के हित में साहसिक निर्णय लेने का साहस चाहिए और वह साहस देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिखाया है।

महोदय, आज इस डिस्कशन के माध्यम से मैं यह आह्वान करता हूं कि जो निर्णय और जो प्रक्रियाएं इस देश में प्रारम्भ हुई हैं, उनके कारण आज 'Ease of doing Business' को लेकर, भारत की ranking को लेकर, भारत के business plans को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का विश्वास बढ़ा है, भारत का foreign exchange बढ़ा है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। इन सब संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, सरकार जिस संकल्प के साथ चल रही है, उसका वातावरण पूरे देश में खड़ा हो, ताकि यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सके, शक्तिशाली देश बन सके। हर

व्यक्ति को मकान मिल सके और हर व्यक्ति का संकल्प 2022 तक पूरा हो सके, इस देश के हर नागरिक का विकास हो सके, देश के अंदर ऐसी भावना बने, धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : धन्यवाद, श्री भूपेन्द्र यावद जी। प्रो. राम गोपाल यादव, आपका टाइम 11 मिनट है।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, जो चर्चा का विषय है, वह बहुत व्यापक है और समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। अपनी बात कहने से पहले एक जनरल बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 20-25 साल से संसद में, इस सदन में या उस सदन में, देश की इकोनॉमी पर, बेरोज़गारी पर और अन्य चीज़ों पर चर्चाएं हमेशा होती रही हैं और इस देश की जनता को आंकड़ों के मकड़जाल में हमेशा ही फंसाया गया है, लेकिन जमीन पर reality कभी कुछ नहीं रही है।

श्रीमन्, अगर हम भूपेन्द्र यादव जी की इस बात को सही मान लें कि जो कुछ इन्होंने किया, वह सब सही था और तभी चुनाव में परिणाम इनके पक्ष में आए, तो आपको यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस ने जो uninterruptedly राज किया, तो इनकी सारी नीतियां सही थीं ! हम तो इस बात से कभी सहमत नहीं रहे हैं। आपकी भी कई नीतियों से हम सहमत नहीं हैं। जब हम इकोनॉमी पर बात करते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि Moody's की rating क्या

कहती है और CRISIL की rating क्या कहती है, लेकिन 80 प्रतिशत लोग न तो इसको जानते हैं और न ही समझते हैं।

(2q-rpm पर जारी)

RPM-KSK/2Q/3.10

प्रो. राम गोपाल यादव (क्रमागत) : महोदय, आज गांवों में लोगों की स्थिति क्या है, क्या उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है, क्या उन्हें सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध हैं, क्या बीमारी की स्थिति में उन्हें दवाएं उपलब्ध हैं, क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा है? अगर है, तो इकोनॉमी अच्छी है और यदि नहीं है, तो फिर आप चाहे जितना कहते रहिए कि इकोनॉमी ठीक है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है।

महोदय, इस राज्य सभा को हम मान लें कि यह हिन्दुस्तान है और इसमें 250 लोग हैं और इनकी पूरी पूंजी, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, वह मान लें कि 250 करोड़ रुपए है। इसमें अगर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो, तो एक साल में 25 प्रतिशत और बढ़ गई और इस प्रकार वह बढ़कर 275 करोड़ रुपए हो गई। अब इनमें से कुछ लोगों के पास 175 करोड़ रुपए हैं और कुछ के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन 10 प्रतिशत ग्रोथ रेट है। वह इनका भी बढ़ा हुआ माना जाएगा, हमारा भी बढ़ा हुआ माना जाएगा और बाकी सबका भी बढ़ा हुआ माना जाएगा। यही इस देश में हो रहा है। वास्तविकता यह है कि गरीब आदमी का कुछ भी नहीं बढ़ा है। अगर आर्थिक स्थिति सुधरी है, तो मुश्किल से 5 या 10 प्रतिशत लोगों की सुधरी है, लेकिन इतनी ज्यादा सुधरी है कि अगर उसका टोटल औसत ले लिया जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा इतना ज्यादा ग्रोथ रेट है।

महोदय, मैं भूपेन्द्र जी से कहना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को चीन से कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। चीन में धान और गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर यील्ड है, वह भारत से दोगुनी है, फिर आप चाहे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे अपने आंकड़े देख लीजिए या फिर इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए। चीन का जो खेती का एरिया है, बड़ा देश होने के बावजूद, वह भारत से आधा है। चीन में जिस लैंड में खेती होती है, वह हिन्दुस्तान से आधा है और हमारे यहां दोगुना है, लेकिन चूंकि यील्ड प्रति हेक्टेयर कम है, इसलिए उसका ग्रोथ रेट छ : प्रतिशत है और हमारा एक या दो प्रतिशत के आसपास झूलता रहता है और कभी-कभी मायनस में चला जाता है। एक बार, डॉक्टर साहब के जमाने में तीन-चार प्रतिशत हो गया था। इस वर्ष 1.5 प्रतिशत है। अगर कृषि का ग्रोथ रेट इतना कम है, तो आप अन्य क्षेत्रों में चाहे जितना बढ़ा दीजिए, हिन्दुस्तान का कृषि पर आधारित जो 60 प्रतिशत आदमी है, वह गरीब रहेगा। उसकी इकनौमी ठीक नहीं मानी जा सकती है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और देश की इकोनॉमी को सुधारना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर लोग रोजगार पाते हैं, उनके ऊपर अब भी निर्भर हैं और जिंदा हैं। उन्हें बहुत प्रश्रय देना होगा।

महोदय, यहां श्री जगत प्रकाश नड्डा साहब बैठे हैं, मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा कि सरकार का स्वास्थ्य पर वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में कुल जीडीपी का केवल 1.3 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों में क्या स्थिति है,

उसे बताकर मैं अपने देश की स्थिति को ज्यादा खराब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री भूपेन्द्र जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिन आंकड़ों को मैं बता रहा हूं, ये अपने ही आंकड़े हैं। ये कोई हमारे या आपके बनाए हुए नहीं हैं। ये सरकार के अधिकृत आंकड़े हैं। मैं आपके ही माध्यम से बता रहा हूं। उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूं। (2 आर/पीएसवी पर जारी)

PSV-SK/2R/3.15

प्रो. राम गोपाल यादव (क्रमागत): सर, 2014-15 में एजुकेशन में GDP का 0.55 परसेंट सार्वजनिक निवेश हुआ, जो 2015-16 में घट कर 0.50 परसेंट रह गया और 2016-17 में यह घट कर 0.49 परसेंट हो गया, तो कैसे बच्चों को और गाँव में रहने वालों को ठीक से शिक्षा मिलेगी? मैं तो मनरेगा वगैरह का और मिड-डे-मील का सार्वजनिक रूप से इसलिए विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग कहने लगेंगे कि इस तरह गरीबों का विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम है ! आप आधार कार्ड से जोड़ दीजिएगा। जिन लोगों को कोई काम नहीं करना है, उनको आधा पैसा पहले दे दिया जाता है। वह उनके अकाउंट में चला जाता है और उनसे ले लिया जाता है कि तुमने कोई काम ही नहीं किया, आधा लो और आधा खा जाओ। इस देश में पैसे की सबसे ज्यादा बरबादी मिड-डे मील और मनरेगा से हुई है, जिससे न जाने कितना काम हो सकता था ! यह मैं ground reality की बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ बोलता हूँ, तो मेरे दिल में कोई पोलिटिक्स नहीं होती। मैंने देखा है कि एक दिन में एक मजदूर को इतना काम करना

चाहिए। ठेकेदार जाता है, बाकायदा उसके सारे ओरिजिनल दस्तखत हैं। वह कहता है, तुम्हें 150 रुपये जो मिल रहे हैं, तुम 75 लो और दस्तखत कर दो, कोई काम नहीं करना है। मशीनों से सब काम हो रहे हैं। काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, राज्य में इसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। यहाँ से आपने कोई एजेंसी नहीं बनायी। हम लोगों की सांसद निधि का जो पैसा है, उसको भी खा जाते हैं। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी। कभी कोई मॉनिटर करने नहीं जाता है। यह स्थिति है।

सर, मिड-डे मील ने यह स्थिति पैदा कर दी है कि प्राइमरी स्कूल्स खत्म हो गये और हर गाँव में मोंटेसरी स्कूल्स खुल गये। लोग कहते हैं कि इनमें तो बस मास्टर और वे लोग रोटी बनाने में और बच्चों को खिलाने में लगे रहते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। बच्चों ने जैसे ही खाना खाया-- आप स्कूलों में दोपहर के बाद जाइए। आप ज़रा गाजियाबाद के आस-पास के गाँवों में चले जाइए, वहाँ बच्चे मिलेंगे ही नहीं। यह जो स्थिति है, धीरे-धीरे बहुत खराब हो गयी है। उसको कैसे सुधारेंगे, यह आप सत्ता वाले लोग जानें। ये सत्ता में बहुत रहे। ये सुधार नहीं पाये। 1947 से लेकर बहुत लम्बे अरसे तक कांग्रेस के लोग, गुलाम नबी जी वगैरह रहे। ये बहुत लम्बे अरसे तक सत्ता में रहे, लेकिन आप जानते हैं, अगर आज ऐसा हाल है, तो उस स्थिति की तरफ आप भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि "निन्दक नियरे राखिये " और निन्दक को प्रताड़ित मत कीजिए। ...(हास्य)... जो सचिव हैं, उनको ऐसा रखिए, सचिव माने सलाह देने वाले लोग, जो राजा की नाराजगी झेल कर भी सही बात बता सकें। ...(व्यवधान)... यह

क्यों नहीं होगा? ...(हास्य)... अगर नेशनल इंटरेस्ट में होगा...(व्यवधान)... देखिए, रुपाला जी हाथ उठा रहे हैं। यह बिल्कुल होगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः राम गोपाल जी, प्लीज़। ...(व्यवधान)...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो छोटे-छोटे लोग हैं, जैसे बुनकर हैं, दस्तकार हैं, ये सब बेकार हुए जा रहे हैं। चाहे मुरादाबाद के पीतल का काम हो, अलीगढ़ के ताले हों, बनारस की साड़ियाँ हों, महुरानीपुर हो या भिवंडी हो, ये सब धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। यहाँ जो सामान बनते थे, उन सब पर, रेशम से लेकर इन सारी चीज़ों पर, चीन के सामानों ने कब्जा कर लिया है। उपसभापति जी, अब सारे खिलौने, भगवान राम, कृष्ण, गणेश ये सब चीन के बने हुए आने लगे हैं। जो atheist हैं, जो ईश्वर में आस्था रखने वाले नहीं हैं, वे चीन में खिलौने बना रहे हैं और हिन्दुस्तान में बेच रहे हैं।

(2एस/वीएनके पर जारी)

VNK-YSR/2S/3.20

प्रो. राम गोपाल यादव (क्रमागत) : दिवाली पर गरीब आदमी जो बिजली की झालर वगैरह बना लेते थे या दीया बेचते थे, वे सब खत्म हो गए। चीन से बनी हुई झालरें आने लगीं और वे दो दिन चलती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, इसलिए सब खत्म हो गए। यह स्थिति हो गई है।

हिन्दुस्तान का रेशम बहुत प्रसिद्ध था, पहले कभी ढाका का मलमल था, बनारसी साड़ियां..... सारी दुनिया में हिन्दुस्तान के जो लोग हैं, रूपाला जी, अमेरिका में आपके

गुजरात के बहुत लोग हैं, मैं कभी-कभी जाता हूँ, तो मुझे गुजरात के ही लोग मिलते हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे सब बनारसी साड़ियां यूज़ करते हैं। गुजरात की साड़ी दुनिया में उन सब जगहों पर जाती है, जहां हमारे लोग रहते हैं और महिलाएं उसको पहनती हैं।...(समय की घंटी)... दुर्भाग्य यह है कि इस देश में नया फैशन आने लगा है, लेकिन हिन्दुस्तान से बाहर साड़ी से बेहतर कोई परिधान नहीं माना जाता है। वे सब बेकार हुए जा रहे हैं। आप हिन्दुस्तान को चीन का dumping ground बनाने से रोकिए, सख्ती से रोकिए, पूरा देश आपके साथ है। देश की economy को ठीक करने के लिए यह जरूरी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, मैं मुश्किल से दो मिनट का समय और लूंगा। हम आपको कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं।

सर, मैं आखिर में एक चीज कहना चाहता हूँ कि यह जो बिजली का per capita consumption है, उससे इस बात का measurement होता है कि वह देश कितना संपन्न है। इस देश में जिस राज्य में बिजली का per capita consumption ज्यादा है, वह राज्य सबसे ज्यादा संपन्न है। ऐसे ही दुनिया में जहां पर बिजली का per capita consumption ज्यादा है, वह सबसे ज्यादा संपन्न देश है। बिजली खपत के मामले में दुनिया का औसत 2429 यूनिट per capita per annum है और हिन्दुस्तान का औसत 734 यूनिट per capita per annum, अमेरिका का औसत 13,000 यूनिट per capita

per annum और चीन का औसत 2,456 यूनिट per capita per annum है, तो हम compare क्यों कर रहे हैं कि हम चीन से आगे जा रहे हैं या फलां से आगे जा रहे हैं? आप बिजली की खपत को बढ़ा कर तीन गुना कर दीजिए और देखिए कि खेती में पैदावार बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। छोटी-छोटी small-scale industries में अभी diesel से जो काम करते हैं, जब वही काम बिजली से करने लगेंगे, तो वह सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि बिजली सस्ती पड़ती है। हालांकि बिजली की दरें सस्ती होने के बाद भी तमाम राज्य उसकी दर बढ़ाते जाते हैं। पीयूष गोयल जी अभी नहीं हैं, पर अब तो वे रेल मंत्रालय में चले गए। कई कंपनियां सस्ती बिजली देने को तैयार होती हैं, लेकिन राज्य सरकारें सस्ती बिजली नहीं देती हैं, दाम बढ़ा देती हैं। अब 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। मुश्किल है, लेकिन फिर भी संयंत्रों को पेट्रोल या डीजल की जगह बिजली से चलाना सस्ता है। उसके जरिए जब उसका consumption बढ़ेगा, तो उससे जो production होगा, उससे लाभ होगा।

अगर आप खेती को लाभकारी बना दीजिएगा.... अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अबकी बार किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। हमारी main crop ही आलू की थी।...(समय की घंटी)... पिछली बार बोलते हुए मैंने कहा था कि मैं तो कभी-कभी आलू खरीद लेता हूँ, पैदा तो करता ही हूँ, तो 10-20-50 लाख रुपए बच जाते हैं, लेकिन अबकी बार पहली बार घाटे में चला गया। इसलिए स्थिति वैसी नहीं है, जैसी प्रचारित की जाती है, लेकिन इस देश में दुर्भाग्य यह है कि कभी इस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, इसको याद रखिएगा। हमेशा नारों पर चुनाव लड़ा जाता है। जब इंदिरा जी के

खिलाफ सारा देश लगा था, तो इंदिरा जी ने धीरे से कहा कि ये लोग मुझे हटाना चाहते हैं, मैं गरीबी को हटाना चाहती हूँ। बस एक sentence और bumper majority. अगर देश में इन नारों पर ही चुनाव जीता जाएगा, तो देश की economy कभी सुधर नहीं सकती है। देश की economy को सुधारने के लिए रचनात्मक कदम उठाएं, सख्त कदम उठाएं।...(समय की घंटी)... Unpopularity बहुत अच्छी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, मैं demonetisation और GST पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत नुकसान हो गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ के बंद हो जाने के कारण सूरत से कितने लोग चले आए। वहां पर हमारे यहां के हजारों लोग काम करते थे, वे सब वापस आ गए। सब छोटी इंडस्ट्रीज़ बरबाद हो गईं, जब कि वही रोजगार देती हैं। जो देश को संपन्न बनाने का काम करती हैं, जो कमेरे लोग हैं, वे सब बेकार हो गए। जब बेकार हो गए हाथ, तो देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now conclude.

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि देश को आंकड़ों से बचाइए। इस देश की जनता आंकड़ों को नहीं समझ सकती। जब 25 साल में मैं नहीं समझ पाया तो गांव में बैठा व्यक्ति क्या समझ पाएगा कि आंकड़े क्या कहते हैं, Moody's क्या कह रहा है, IMF क्या है, ITRD क्या है, इसे कोई नहीं जानता। इन शब्दों के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

(2टी/एनकेआर-वीकेके पर आगे)

-YSR/VKK-NKR/2T/3.25

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to see the positive side also. The Central Government has allotted 57,000 seats in the BPO sector to Tamil Nadu. I thank the hon. Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad. But it is not sufficient because most of the engineering colleges have been closed and also there is no campus interview in any of the educational institutions. So, kindly take note of that fact. I request the Central Government to allot more number of seats in the BPO sector.

(THE VICE-CHAIRMAN, DR. SATYANARAYAN JATIYA, in the Chair)

Sir, with regard to agriculture in Tamil Nadu, especially on Kaveri, the dispute is well known. Now, from Kaveri, we are not getting water. Our State is a manufacturing State. Of course, we will get compensation under GST. No doubt about it. It is consumption-based tax. But agriculture has to be revived. The banking system is already not functioning in favour of the agriculturists because all the agriculturists are wilful defaulters and not able to repay it.

Now, I have received information which is very, very valuable information, from Mr. Nitin Gadkari, the hon. Minister in the Central Government. He has got two proposals to bring water to Kallanai Dam. I welcome the proposals. I urge the hon. Minister, Mr. Nitin Gadkari, very sincerely and humbly to implement the proposals and bring water to Kallanai Dam. It is an engineering marvel. Even with modern technology, the dam cannot be constructed. Technique-wise, it is second in the whole world. If he really brings water to Kallanai Dam, he will be the second Karikala Cholan because the Kallanai Dam was constructed by Karikala Cholan, the Great King, one thousand years ago or two thousand years ago. Nobody knows. But even now, it is intact. There is no damage. So, Mr. Nitin Gadkari is going to be the second Karikala Cholan of Tamil Nadu. Now, it all depends on the finance to be provided. I do not know the exact functioning of how he is going to get it. The hon. Finance Minister is very much here. I am very happy and if Kallanai Dam gets water, all credit goes to our hon. Prime Minister because he is taking care of the poor people in a proper perspective. We depend on our hon. Prime Minister. If water is brought to Kallanai Dam and if the proposal is implemented, then definitely, entire Tamil Nadu will become very, very prosperous.

With regard to health sector, hon. *Amma* had written many letters to the Central Government to allocate AIIMS hospital and college to Tamil Nadu. In pursuance of the letters written by hon. *Amma*, the Central Government, very graciously, allotted one to Tamil Nadu State. But, it is yet to be established. It seems there is some dispute with regard to the location, but the Central Government must take a decision, a final decision, as early as possible and establish AIIMS in Tamil Nadu to fulfil the dream of hon. *Amma*.

(Contd. by RL/2U)

-BHS/RL-DS/3.30/2U

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (CONTD.): And, if water is provided and agriculture is revived, then, by and large, the rural unemployment problem can be solved to a certain extent. But, now the aspirations of the rural people are more and more, more than the urban people because they want to own very costly cars; they want to enjoy the internet benefits. So, I urge the Central Government to take appropriate steps to provide internet connection to the rural area and also, at the same time, electricity is also to be provided so to have uninterrupted internet connection. That has to be done by the Central Government and the State Government. Sports

activities must be encouraged among the rural people. So, we must tap the talent available in the rural areas and very good institutions must be established by the Central Government. They must help us. Regarding the scholarship provided to the SC/ST students, those who are studying in the colleges, some thousands of crores of rupees have to be disbursed by the Central Government to the State of Tamil Nadu. Hence, the hon. Minister of Social Justice and Empowerment the other day promised me that in the month of January, it will be disbursed. I hope he will do the needful and help the SC/ST students. Another thing, I came to know, in the Central Government, OBC vacancies are not filled up. It is the sorry state of affairs because OBC people are not intelligent enough to write the appropriate examinations and to occupy the positions. So, those posts must be carried over and opportunity must be given to the candidates belonging to the OBC and their sensitization has to be created so that the posts are not filled up by other candidates. This is my humble request. And, then, regarding the startups—it is well-known to the hon. Finance Minister and it is already published in the newspapers, only for the sake of completion I am submitting this— I am sure, our hon. Finance Minister would have taken care of their problem because the startup companies are getting IT notices,

treating the investment they received as income. According to the entrepreneurs, they say that it is not income and it is only a genuine investment. But, according to the IT Department, they are changing the colour from black to white. So, it has to be taken care of by our hon. Finance Minister. I am very happy and I welcome the BJP President, Shri Amit Shah because now I feel that the demands on behalf of the State Government will be taken care of by the BJP President, hon. Prime Minister and the other Council of Ministers. So, these are all my requests and demands on behalf of the State Government because already the agriculture activity has come to an end. As such, no agricultural activity is taking place because of the scarcity of water. All the agriculturists have become poor labourers in the textile units at Tiruppur, Coimbatore and Erode. It is a sorry state of affairs. So, please, restore our dignity by providing water and do the needful. I thank the Central Government and I also thank the Chair for giving me this opportunity.

(Ends)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (WEST BENGAL): Sir, the citizens of the country are deeply concerned with the economic situation prevailing now because in every sector, in every field of economy, the Government has

failed miserably. I am saying so because of the introduction of demonetization which, according to the Supreme Court, was a carpet bombing of the citizens and secondly, the mismanagement of the GST. This double shock has created the situation. If we go through the figures quickly, first of all, this G.D.P. growth about which many Members have talked.

(CONTD. BY KR/2W)

KR/MCM/2W/3.35

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (CONTD.): I remember when we were discussing the demonetization issue, Dr. Manmohan Singh in this House, he was on record, said that according to his estimate there will be 2 per cent decline in the GDP growth. Now everybody is saying that the GDP growth has already declined compared to 8 per cent in 2015-16, it came down to 7.1 per cent in 2016-17. Now even the SBI Reasearch Chief Economist says, “It is difficult for the GDP to cross 7 per cent this fiscal.” Similarly other people have said. If we look at the gross fixed capital formation, the investment rate measured as the ratio of the gross fixed capital formation to GDP at current prices was further down to 26.9 per cent from 28.1 per cent indicating that corporate have not been investing in capital creation. This is a major area of concern.

Second is the industrial growth. Manufacturing and electricity sector output were lower compared to the previous years. The use-based classification reveals that barring non-durable consumer goods, all other sectors witnessed lower growth rates. The forecast for industrial growth for the year is only 4-4.5 per cent.

Agriculture is a major area. "India lives in villages" was said by Gandhiji. Our farmers were getting remunerative prices. They have resorted to distress sales. लाचार है किसान, उसको दाम नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में, दूसरी जगह में और सारे हिन्दुस्तान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि बी0जे0पी0 का जो मेनिफेस्टो है, शायद अमित शाह जी ने वह मेनिफेस्टो रिलीज़ किया था, मुझे मालूम नहीं, सब्जेक्ट टू करेक्शन, उस मेनिफेस्टो के पेज-19 में बताया गया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से किसानों का दोगुना प्राइस हम एन्श्योर करेंगे। अभी तक हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है।

Sir, the Government finances, as per the latest data released by the Government for the period April-November, 2017, the fiscal deficit is 112 per cent of the target, while the revenue deficit is 152.2 per cent of the budgeted amount. This has prompted the Government to announce an additional borrowing programme of Rs.50,000 crores for the year. The fiscal deficit would go up to 3.5 per cent of GDP for the financial year 2018 which has

been estimated by some experts. I am not an expert but it is the view of the experts.

Sir, so far as the banking sector is concerned, we have discussed it at length. I need not repeat it. But the credit growth to manufacturing and services for April-October is negative while that to agriculture and personal loans segment is 7.7 per cent.

Regarding external sector, while growth in exports for the period April-November, 2017 is a little better than the earlier term, imports too surged by 21.9 per cent leading to a higher trade deficit of $100 billion compared to $68 billion last year. From $68 billion to $100 billion is the trade deficit. Now the Foreign Direct Investment has increased. Foreign Direct Investment has no doubt increased. But whether it has created jobs in the country, I have every doubt because the country has been dragged through ten years of jobless growth, no doubt. This is what the BJP manifesto has promised to the nation. "Under the broader economic revival, BJP will accord high priority to job creation and opportunities for entrepreneurship."

(Continued by 2X/KS)

KS-GS/2X/3.40

श्री सुखेन्दु शेखर राय (क्रमागत): आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने आगरा में आम सभा को संबोधित करते हुए बोला था और दूसरी जगह भी बोला था कि हम हर साल दो करोड़ जॉब्ज़ क्रिएट करेंगे। आम सभा को संबोधित करते हुए, यह नेशन को बताया गया था। इसके लिए मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं यह चर्चा कर रहा हूं कि ऐसा प्रधान मंत्री जी ने बोला था। अब देखिए क्या हाल है? बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पहले तीन साल में 2.47 मिलियन से घटकर 1.51 मिलियन जॉब्ज़ रह गए हैं। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है! The unemployment situation is such that they could not create jobs. Jobs are becoming less and less. According to the Organization of Economic Cooperation and Development report published in 2017, the rate of employment has declined and job creation has not kept pace with the growing working-age population. More than 30 per cent of the Indians aged between 15-29 years are neither in employment, nor in education and training. आप स्किल डेवलपमेंट, स्टार्ट-अप जैसी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आएं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रोजगार नहीं बढ़ा है। हमारा देश युवाओं का देश है और इस देश के युवाओं का हाल क्या है ? 30 per cent between the age-group of 15 to 29 years are not in employment; they do not have any jobs. यह हाल हमारे देश के युवाओं का है। जब हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और हम आगे बढ़ेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? Sir, I would now like to conclude because the time is running out. I would just make my last

point. यह लास्ट प्वाइंट है। मैंने हमेशा बोला है, हमारी पार्टी ने मांग की है कि "पनामा" पेपर ने जो नाम निकाले थे, उसके बाद जो "पैराडाइज़" पेपर आया। "पनामा" पेपर ने 500 से अधिक इंडियन लोगों के नाम निकाले थे। वह लीगल था या इल्लीगल था, इसकी जांच सरकार करेगी, उसके बारे में तीन साल में क्या जांच हुई, उसके बारे में हमें पता नहीं है। इस बीच में "पैराडाइज" पेपर आ गया, उसमें और 700 इंडियन लोगों के नाम जुड़ गए, जिन्होंने फर्ज़ी कम्पनी बनाकर इल्लीगल और सीक्रेट डीलिंग की थी। हम चाहते हैं कि इनके बारे में सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए और सरकार बताए कि इसमें कौन-कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं?

सर, मेरा लास्ट प्वाइंट है। हमने पहले बोला था कि super financial emergency like situation देश में पैदा हो गई है। इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि बैंक में पैसा रखना सही होगा या नहीं होगा और सारे देश की जनता चिंतित है कि इसके लिए सरकार बिल ला रही है। अब सरकार ने insolvency and bankruptcy code को लगाया है। इसमें बैंकों को insolvent, bankrupt डिक्लेयर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऐसा एक माहौल पैदा हो गया है। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि वह ब्लैक मनी के ऊपर एक व्हाइट पेपर निकाले, जैसा कि डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निकाला था। उसके बाद तीन-चार साल में क्या हुआ, यह हम जानना चाहते हैं, धन्यवाद।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : श्री अनुभव मोहंती। आपके पास पांच मिनट बोलने का समय है।

श्री अनुभव मोहंती (ओडिशा) : सर, मेरे लिए पांच मिनट का समय बहुत है। Sir, decentralization of the economy started in the early '90s, which came on track at the turn of the Century. The idea was to create an environment for investment, to lift the economy to a six per cent average growth of the national GDP annually, to strengthen the rural infrastructure and a sustainable agro-economy. To achieve all these, heavy investment in infrastructure was required, with a conducive manufacturing environment and a policy change. The then NDA Government, under Shri Vajpayee, put all these things into perspective to carry forward the Indian dream, the dream of the Indian youth. Then came the UPA Government. The Government under Dr. Manmohan Singh carried it forward, but got bogged down by the economic slowdown and policy paralysis, because they couldn't take any decisions on economic fronts in their last three years of governance.

(CONTD. BY RSS/2Y)

RSS/2Y/3.45

SHRI ANUBHAV MOHANTY (CONTD.): This resulted in their failure, and, in 2014 again, the NDA Government came to power under the leadership of Shri Narendra Modiji. Now, the season came of high hopes, high aspirations and high dreams. The Prime Minister, Shri Narendra Modiji made many tall promises. It would take a lot of time to cite all the promises, but, I would cite a few promises out of the lot more promises. Number one is, jobs for the youths, two crore jobs per year. They have not given even five lakh jobs in four years. Second is, heavy investment in infrastructure development, which is yet to happen. Third is, conducive atmosphere for manufacturing which is yet to take off. Fourth is, the smooth policy decisions in finance and governance which has gone haywire. Lastly, the promise of a stable agricultural growth which has gone terribly down, Sir. In the last four years since this Government has come to power, we have been only hearing nationalistic speeches, tall promises, and a story of dream which has no conclusion at all. As of today, all the parameters of the economic indicators are showing a downward trend with a very little hope of coming back to track in a year's time. Hence, the situation of desperation amongst the countrymen, and especially, the youth of the nation is slowly setting in. We cannot keep on befooling ourselves any more from the reality by taking

solace on the foreign agencies ratings. Sir, education, health, women and child welfare, agriculture, all these sectors are slowly showing heavy downward trend because of lack of investment by the Government. If I am not wrong, Sir, I would seek your permission to ask the Government one question. Will they not agree with me that their lack of investment in social sectors is resulting in promoting Naxalism in the country? Will they disagree with me? At one point of time, the Government was spending thousands of crores of rupees to stop Naxalism, and, at the same time, when we are investing very less money in social sectors, and that is giving rise to Naxalism, is it not contradictory in itself? So, I would like to ask the Government a question on this point. I hope, they clarify. So, no wonder, today, our engineering and MBA pass outs are running from pillar to post to get a salesman's job. Is this not a * on the present Government? The engineering and MBA pass outs, doctors, are asking for salesman's job, and the Government must feel * of this.

Sir, in the Monsoon Session, we had a discussion on compulsory education for all. In that, myself and my party had requested the Government to rethink on that. When we are demanding a minimum qualification of 12th pass for any kind of employment, then, why are we not considering compulsory education till 12th standard, why till standard eight, or at the age of fourteen? When the minimum qualification required for employment is 12th standard, it should be made

compulsory by the Government that the compulsory education for all should be till 12th standard, or, at the age of eighteen.

Sir, now, demonetization and GST has added to the very serious problem of unemployment. Sir, not a single sector in the country has been

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

left unharmed. I belong to the film fraternity. I would like to say on that. Film industry gives a lot of employment. A lot of employment is being generated by the film industry. I know they have a big smile on their face when I am speaking on the film industry, but, it is quite genuine that you are to think very, very, honestly on this issue because lakhs of people are employed through film industry, and GST has broken down the bones of the film industry in the whole of the nation. A lot of people have been rendered unemployed. As per the report of the Centre for Monitoring Indian Economy, there has been a loss of fifty lakh jobs in the country in the period of January 2017 to April 2017. It is more than obvious that the Government policies and various initiatives, like, 'Make in India', 'start-ups,' have not yet given the desired results on the job scenario.

(contd. by 2z/KGG)

KGG-ASC/2Z/3.50

SHRI ANUBHAV MOHANTY (contd.): So, Sir, how can jobs be created? What will be the youth dreaming for? How will his or her aspirations be fulfilled? Certainly not by *Deshbhakti* speeches and certainly not by *jumlas* that were made in 2014. The time is very less; the time is running out. In 2014, when the entire nation thought of high hopes, high aspirations and

high dreams, now it is changing a bit and very strongly; 'high' has been substituted by 'fake', Sir--fake hopes, fake aspirations and fake dreams. If the Government does not put a strong view on these issues, this unemployment matter in 2019 is going to give a strong setback that you have never even imagined of. Thank you so much, Sir.

(Ends)

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, in the real estate industry, if you have a setback, you will create taller buildings after that. If there is a setback in the real estate project, ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने पर परवानगी में मिलती है परमिशन। मुझे लगता है कि मेरे मित्र अनुभव जी शायद उसका जिक्र कर रहे हैं, उनको जैसे पीछे धकेलेंगे, तो और ऊंचाई पर चढ़ेंगे।

....(व्यवधान)....

श्री अनुभव मोहंती : आप मुझे धकेल दीजिए, लेकिन देश को पीछे मत धकेलिए। देश आपको बहुत पीछे धकेल देगा।

श्री पीयूष गोयल : यह फिल्म का सेट नहीं है।

श्री अनुभव मोहंती : मैं देश की बात कर रह था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : मेरा अनुभव यह है कि अब अगले वक्ता को बोलना चाहिए।

श्री हरिवंश : उपसभाध्यक्ष जी, देश की तस्वीर जिन चीजों से बदलने वाली है या तय होने वाली है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): हरिवंश जी, आप अच्छा बोलते हैं। आपके लिए चार मिनट का समय है।

श्री हरिवंश : सर, आपने एक मिनट ले लिया, इसलिए मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप इसमें एक मिनट बढ़ा दें।

उपसभाध्यक्ष (सत्यनारायण जटिया) : ठीक है।

श्री हरिवंश (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, देश की तस्वीर जिन चीजों से तय होने वाली है, आपने उन विषयों पर आयोजित इस अल्पकालिक चर्चा में में मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। स्वाभाविक है कि GDP growth की चर्चा, export की स्थिति, trade imbalance की जो स्थिति है, manufacturing and construction की बात है, industrial growth की बात है, fiscal deficit की बात, capital formation की बात, rural India की बात, किसानों के चेलैंज की बात, बैंकों के NPAs की, regional disparity की बात, social inequalityकी बात होगी । कुछ जगहों पर चेलैंजेज़ हैं, कुछ पर positive indicators, हैं और कुछ पर सीरियस चेलैंजेज़ हैं सबसे बड़ी बात है कि सरकार इनको बहुत संसिटिविटी के साथ सीरियसली एड्रेस करना चाहती है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह की legacy बताई है, वह माननीय वित्त मंत्री जी बताएंगे। जो legacy हम जैसे सामान्य लोगों को पता चलती है कि सरकार को कैसी मिली, यह मैं नहीं कह रहा हूं। जो दुनिया के Top Economists

हैं, जिनको फ्यूचर के लेनिनवाद के पुरस्कार मिलने की बात हो रही है, जिन्होंने गरीबी पर अध्ययन किया है, उनमें से Lucas-Chancel and Thomas-Piketty ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने भारत के बारे में विशेष अध्ययन किया है। 1922-2014 के बीच ये क्या कहते हैं 'Sharp increase in wealth concentration from 1991 to 2012 particularly after 2002 to 2014.' They conclude, 'India has only been really shining for the top ten percentage of population, roughly 18 million people, in 2014 as against the middle 40 per cent.' इनके सत्ता में आने से पहले भारत सिर्फ एक परसेंट लोगों के लिए चमक रहा था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया के top Economists कह रहे हैं। वर्ष 2002 से 2014 के बीच कौन लोग सत्ता में थे, जो top ten per cent थे, उन्होंने उनमें से भी सिर्फ एक परसेंट के लिए काम किया। वह समाजवादी लोगों की सरकार थी, समाजवादी दर्शन की बात करने वाली सरकार थी। Again I quote: "Economists say that top one per cent of the earners captured less than 21 per cent of the total income in the late 1930s before dropping to six per cent in the early 1980s and rising to 22 per cent; today India, in fact, comes out as a country with the highest increase in top one per cent income share concentration over the last thirty years. सबसे कम आमदनी यानी एक परसेंट लोगों की आमदनी बढ़ने वाली सरकार आज इधर बैठी हुई है।

सर, इन्होंने गरीबी की बात कही है और बढ़ाई एक परसेंट लोगों की अमीरी।

दुनिया की सबसे unequal society भारत को बनाया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह तो

दुनिया के Top Economists लिखते हैं। ...(व्यवधान)...यह Thomas-Piketty की रिपोर्ट है, मैं quote कर रहा हूं। आप यह देख लें। आनन्द जी, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ....(व्यवधान).... मैं अभी टेबल पर रख देता हूं। ....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (सत्यनारायण जटिया) : आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री हरिवंश : इसके लिए आपको समय देना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): Anandji, he is not yielding.

श्री हरिवंश : यह गरीबों की सरकार की उपलब्धि...(व्यवधान)... सबसे भ्रमित...(व्यवधान)...

श्री उपसभाध्यक्ष (सत्यनारायण जटिया) : दूसरा कुछ तो जायगा नहीं ...(व्यवधान)... दूसरा कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए आप बोलिए।

(3A/SCH पर आगे)

SKC-SCH/3A/3.55

श्री हरिवंश : सर, इन लोगों ने और क्या किया, मैं आपको बताता हूं। "For the top 0.001 per cent citizens, the growth rate during the period from 1990 to 2014 was 2,776 per cent." यानी चीन, अमरीका और फ्रांस से भी ज्यादा रहा। मैं माननीय मनमोहन सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन एक अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री के रहते हुए यह सब हुआ और यह दुनिया के top economists ने बताया है। ...(व्यवधान)... हमारे मित्रों को अभी मैं और भी बताता हूं, आप सुनने का धैर्य रखिए।

सर, अब इस सरकार ने क्या किया, यह भी मैं आपको बता रहा हूं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आप लोग आपस में बात न करें। No cross talking, please.

श्री हरिवंश : सर, Income tax submit होने के बाद, 21 दिसम्बर को अखबारों में यह रिपोर्ट आई है, जिसमें 2015-16 के आयकर रिटर्न से जुड़े डेटा जारी किए गए हैं। उसका निष्कर्ष क्या है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं - "देश में करोड़पतियों की संख्या 23.5 % बढ़ी।" लेकिन उसमें सबसे remarkable बात यह थी कि इन करोड़पतियों की कुल आय 25% घटी है। यह इस सरकार की उपलब्धि है, जो शायद इनको पता नहीं है।...(व्यवधान)... मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने अमीरी घटाई और अमीरों की अमीरी लेकर गरीब लोगों को देने का काम किया है, जो अमीरी उस सरकार ने एक प्रतिशत लोगों को दी थी। यह इस सरकार की उपलब्धि है।

सर, 'गरीबी हटाओ' के नाम पर जो सरकार आई थी, उसके बारे में भी मैं उन लोगों को कुछ याद दिला देना चाहता हूं, जो बेचैन हो रहे हैं। गरीबी हटाओ के नाम पर युवा तुर्कों की क्या भूमिका थी, यह हम सब जानते हैं। चन्द्रशेखर जी ने 1971 में चुनाव जीत कर आने के बाद 'Young India' में यह लिखा, "सबसे पहले हमारा काम, गरीबी हटाने के लिए हमने जो वादे किए हैं, उनको पूरा करना होना चाहिए", लेकिन यह बात कहने के कारण बदले में उनको चार वर्षों की जेल मिली। दूसरी तरफ इस सरकार ने बिना वादे किए ही गरीबी हटाने का काम किया।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आपका समय हो गया है।

श्री हरिवंश : सर, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : शुरू किया है, तो खत्म भी कर दीजिए। मैं अगले वक्ता का नाम बुला रहा हूं, श्री टी.के रंगराजन।

रेल मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : सर, हम अपना टाइम इनको दे देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है।

हरिवंश जी, आप अच्छा बोलते हैं और आपने बोल लिया है। अब किसी और मौके पर आप बोल लीजिएगा।

श्री हरिवंश : सर, दो मिनट और दे दीजिए।

सर, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ है, दुनिया के पांच top economists ने इसका अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है, "इस economic inequality का असर यह हुआ, that children whose parents are in the top one per cent by income are ten times more likely to become inventors." यानी अब आइंस्टीन बड़े घरों के लोगों के यहां पैदा होंगे, यह इन्होंने किया था, लेकिन अब उस व्यवस्था को एक गरीब घर से आए व्यक्ति, हमारे प्रधान मंत्री ठीक करना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आपका समय समाप्त हो चुका है, आप एक सेंटेंस में अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री हरिवंश : सर, मुझे एक मिनट और दे दीजिए।

सर, अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं कि कैसे इस सरकार ने लीकेज बंद करने का काम किया है। इन्होंने आधार का प्रयोग किया, DBT का प्रयोग किया, जिससे देश में income taxpayers की संख्या बढ़ी, income का base बढ़ा। इस तरह मैं कह सकता हूं कि सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिससे बहुत बेहतर चीज़ें हो रही हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी, धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री जयराम रमेश : सर, हरिवंश जी का पिछला भाषण यहां से था, उस समय ये बिल्कुल विपरीत बोले थे।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : श्री टी.के. रंगराजन। रंगराजन जी, आपके पास चार मिनट का समय है, कृपया समय का ध्यान रखिएगा। You have got only four minutes. ...(Interruptions)...

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, this is a very important subject. I would like to refer to the Treasury Benches. Shri Bhupender Yadav rightly stated that the UPA Government suffered from a policy paralysis. We had criticized that. We never accepted the neo-liberal policies of the UPA Government that suffered from a policy paralysis, but, what about the NDA Government? Their Government is in the ICU. I don't think it would ever come out of the ICU of the hospital! When it comes out, the body would be finished. This Government would be finished in 2019.

Now, what is happening? The economy is in an absolute shambles. India has risen in the 'Ease of Doing Business' rankings, but for whom? It is loudly remarked 'ease of doing business', 'ease of doing business', but India is actually going down in the rankings on global hunger. You must remember that.

(CONTD. BY KSK/3B)